3 सवालों के घेरे में भारतीय शिक्षा तंत्र

5 नई पीढ़ी की राजनीति का उभरता चेहरा

6 एक चेतावनी है वेनेजुएला का भूकंप

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 08 प्रति सोमवार, 29 जून 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

टीकमगढ़ सीएमओ ओमपाल भदौरिया के तानाशाही से परेशान नगरवासी

नियमों को ताक पर रखकर कर रहे करोड़ों का भ्रष्टाचार

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

वर्तमान में टीकमगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमपाल सिंह भदौरिया चर्चाओं के केंद्र में हैं। भदौरिया के कारनामों और करतूतों की जैसे-जैसे परतें खुलती जा रही हैं वैसे-वैसे ही इनके संरक्षणकर्ताओं के चेहरे भी बेनकाब होते जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के मुखिया संजय दुबे के बाद एक और चेहरा सामने आ रहा है जो भदौरिया को पूरा संरक्षण दे रहा है और वो चेहरा है टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर। कृष्णा गौर के कृपापात्र बनकर भदौरिया कई गैर कानूनी कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कृष्णा गौर की अनदेखी के कारण ओमपाल सिंह पूरे नगरपालिका प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। करोड़ों के बजट की बंदरबाट करने में जुटे हैं। ठेकों में दलाली, उगाही में दलाली और भष्टाचार में कमीशनखोरी खुलेआम हो रही है। लेकिन भदौरिया के संरक्षणकर्ता आंखों में पट्टी बांधकर तमाशा देख रहे हैं।

सीएमओं के आदेश पर अस्थाई दुकानों एवं ठेलों पर चलाया बुलडोजर

गरीब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उनके ठेले न तोड़ने की गुहार लगाते रहे, परन्तु मौके पर मौजूद टीकमगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा बल्कि गरीब तबके के छोटे दुकानदारों को

डांट-फटकार लगाने के साथ उन्हें ठोकर मारी और उनके रोजगार को उनके ही सामने जमींदोज कर दिया। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी कार्यवाही के पहले एक प्लान तैयार किया जाता है, परन्तु यहां बगैर प्लान के सीधा बुलडोजर चलाकर गरीब दुकानदारों के रोजगार को छीनने के साथ उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है है कि अगर आप एक स्थान से दुकानदार एवं ठेले वालों को हटा रहे हैं तो फिर आपको उनकी उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए, किन्तु यहां ऐसा नहीं हुआ। टीकमगढ़ प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पाया कि यहां हटाए गए ठेले वालों को अब कहां अपना रोजगार करना होगा। उनका तो केवल यही मकसद था कि कलेक्टर साहब कार्यवाही से खुश हो जाए। (शेष पेज 2 पर)

ग्रामीण विकास को नई गति दे रहा छत्तीसगढ़ का मत्स्य मॉडल

जशपुर से पूरे प्रदेश तक मत्स्य क्षेत्र में विकास का नया अध्याय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की पहचान लंबे समय तक कृषि प्रधान राज्य के रूप में रही है, लेकिन अब कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई गति प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र को अभूतपूर्व गति दी है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक पद्धतियों, आधारभूत संरचना के विकास, प्रशिक्षण और उदार अनुदान आधारित योजनाओं के कारण हजारों मत्स्यपालक आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में कृषि के साथ-साथ मत्स्य पालन को भी ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण धुरी बनाया है। राज्य सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि करना और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। यही कारण है कि मत्स्य पालन अब परंपरागत व्यवसाय की सीमाओं से निकलकर आधुनिक उद्यम का स्वरूप ग्रहण कर चुका है।

मत्स्य पालन बना ग्रामीण समृद्धि का आधार

प्रदेश सरकार की योजनाओं के प्रभाव से आज छोटे और सीमांत किसान भी मत्स्य पालन को अतिरिक्त आय के प्रभावी साधन के रूप में अपना रहे हैं। जिन किसानों के पास सीमित कृषि भूमि है, वे तालाबों और जलाशयों का उपयोग कर बेहतर आमदनी अर्जित कर रहे हैं। (शेष पेज 3 पर)

दूरदर्शी नेतृत्व, विकास की सोच और मध्यप्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है कमलनाथ

राज्यसभा में मप्र को मिल सकती थी मजबूत आवाज

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे नेता हुए हैं जिनकी पहचान केवल राजनीतिक पदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके कार्यों, प्रशासनिक दृष्टि और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें जननेता के रूप में स्थापित किया। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। लंबे संसदीय अनुभव, केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रभावी भूमिका और मुख्यमंत्री के रूप में विकासोन्मुखी दृष्टिकोण के कारण उन्हें आज भी मध्यप्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच यह चर्चा भी समय-समय पर उठती रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया होता, तो उनके अनुभव और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संपर्कों का लाभ मध्यप्रदेश को और अधिक मिल सकता था। (शेष पेज 2 पर)

उच्च अधिकारियों के कृपापात्र से निडर हो गये भदौरिया, प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का भी मिल रहा संरक्षण

(पेज 1 का शेष)

1.34 करोड़ रुपए साफ हो गए, लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड के पीछे की तरफ अब भी जला रहे कचरा

स्वच्छता अभियान के तहत टीकमगढ़ शहर से निकलने वाले कचरे को पूरी तरह से साफ करना टीकमगढ़ प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल हैं। लेकिन सीएमओ साहब स्वच्छता में नगर को साफ-सुथरा दिखाने के चक्कर में नित नये कारनामें कर रहे हैं। फर्जी फोटो खिंचवाकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। जबकि हकीकत में कहानी कुछ और ही है। नयाखेरा के पास बने नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में सालों से जमा कचरे को हटाने के लिए नपा ने लीगेसी वेस्ट डंप साइड के लिए 3.17 करोड़ का टेंडर ओमट्रेक्स फर्म को दिया था। फर्म को यहां से पूरा कचरा हटा कर उसका निस्तारण करना था। इसके लिए कंपनी को 70 लाख रुपए का एक भुगतान किया जा चुका है, जबकि 65 लाख के दूसरे बिल को नपा अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक ने संदेह जताते हुए रोक दिया है और इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने की नोटशीट लिखी है।

मशीनें बंद, कचरा अब भी आग के हवालेः कचरे को पृथक कर उनका निस्तारण करने के लिए नगर पालिका द्वारा 5 मशीनों को स्थापित किया गया है। यह मशीनें पिछले एक साल से अधिक समय से लगी है, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो सकी है। यहां पर बना टीनशेड भी क्षतिग्रस्त हो गया है। जबकि इन मशीनों का उपयोग सूखे, गीले कचरे को अलग करने के साथ ही प्लॉस्टिक को प्रसंस्कृत किया जाना था तो गीले कचरे से खाद बनाई जानी थी, लेकिन यह योजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है। यहां पर डाला जा रहा कचरा अब भी आग के हवाले किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर खर्च किए गए 1.35 करोड़ रुपए पर भी सवाल उठ रहे थे। मौके पर दिखाई दे रहा था कि काम में लापरवाही तो हुई है।

नपा टीकमगढ़ में की गई अनियमितताओं की जाँच के संबंध में लिखा था पत्र

दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल एवं उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को नगरपालिका परिषद टीकमगढ में की गई अनियमितताओं की जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में पत्र लिखा गया था। नगर पालिका परिषद, टीकमगढ के अध्यक्ष द्वारा दुकान आवंटन, अमृत 2.0 योजना, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, संजीवनी क्लीनिक, निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, सामग्री क्रय एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति आदि में की गई अनियमितताओं संबंधित शिलायत की जाँच करने हेतु जाँच दल गठित कर, बिन्दुवार जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़ में हुई विभिन्न आर्थिक अनियमितताओं एवं नियम विरूद्ध कराये गये कार्यों के संबंध में निकाय के 16 पार्षदों द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के समक्ष शिकायत कर जांच कराने का अनुरोध किया गया था।

लोग पूर्ण बजट कह सकते हैं, लेकिन मैं 8 महीने का बजट कहूंगा: सुवेंदु अधिकारी

-अमित राय

जगत प्रवाह. कोलकाता। राज्य का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इस बजट को पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के उद्देश्य से विकास और विरासत का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग इसे 'पूर्ण बजट' कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे "आठ महीने का बजट" कहूंगा। चूंकि हमारी सरकार का कार्यकाल दो वित्तीय वर्षों के बीच आता है, इसलिए हमें पूरे 12 महीनों का बजट प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। पिछली सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक चार महीनों के लिए एक 'वोट ऑन अकाउंट' पेश किया था, जिसके माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था संचालित हो रही थी। वित्तमंत्री डॉ. स्वपन दासगुप्ता ने 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। "इस बजट में रोजगार सृजन के लिए मेरी लंबे समय से प्रस्तावित "त्रिधारा" अथवा त्रिशक्ति" योजना को शामिल किया गया है:

सरकारी रोजगारः इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख नई नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 20,000 पुलिस्कर्मी तथा 50,000 शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्रोफेसर और शैक्षणिक कर्मचारी शामिल होंगे। शेष 30,000 नियुक्तियां विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर की जाएंगी।

निजी उद्योग और निवेशः फूड प्रोसेसिंग और एमएसएमई क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए लैंड सीलिंग कानून की समीक्षा की जाएगी। 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्योगपतियों को पंचायतों या स्थानीय निकायों से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

व्यापार और आत्मनिर्भरताः प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करने में राज्य सरकार बड़ी भूमिका निभाएगी।

अन्नपूर्णा भंडार एवं ड्रॉप-आउट रोकथामः महिलाओं को 3,000 की सहायता पहले ही 28 लाख लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है। 1 जुलाई से अतिरिक्त 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं के खातों में राशि भेजी जाएगी। इसके लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्राओं के ड्रॉप-आउट को रोकने के लिए 50,000 की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

मातृ वंदना एवं पोषण किटः पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार 16,000 और जोड़ेगी, जिससे कुल सहायता 21,000 तथा 5 पौष्टिक किट हो जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा के लिए 'पिंक कार्ड' शुरू किया जा रहा है। महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों से युक्त दो नई बटालियन (दुर्गा स्क्वाड) बनाई जाएंगी।

युवाओं के लिए भत्ताः आगामी अक्टूबर से स्नातक युवाओं को 3,000 प्रति माह तथा गैर-स्नातकों को 2,000 प्रति माह दिए जाएंगे (जिनके परिवार की मासिक आय 1 लाख से कम है)।

18 माह का कार्यकाल, लेकिन विकास की लंबी छाप छोड़ गए कमलनाथ

(पेज 1 का शेष)

यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कमलनाथ केवल प्रदेश स्तर के नेता नहीं रहे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

विकासवादी राजनीति के पक्षधर रहे कमलनाथ

कमलनाथ की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी विकास केंद्रित सोच रही है। उन्होंने हमेशा बुनियादी ढांचे, उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक विकास, वाणिज्य और आधारभूत संरचना से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया। उनकी पहचान ऐसे नेता के रूप में बनी, जो केवल राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने की क्षमता रखते हैं।

18 माह का कार्यकाल, लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णय

दिसंबर 2018 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ को अपेक्षाकृत कम समय मिला। लगभग 18 माह के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसी पहलें शुरू कीं, जिनकी चर्चा आज भी राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में होती है। किसानों की कर्जमाफी का निर्णय उनकी सरकार की प्रमुख पहलों में शामिल रहा। इसके अलावा निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने, युवाओं के लिए रोजगार सृजन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में भी प्रयास किए गए। प्रदेश में निवेश आधारित विकास की अवधारणा को उन्होंने नई गति देने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में यह संदेश देने की कोशिश हुई कि मध्यप्रदेश केवल कृषि आधारित राज्य नहीं, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

उद्योग और निवेश के प्रति विशेष दृष्टिकोण

कमलनाथ लंबे समय तक उद्योग और वाणिज्य से जुड़े मंत्रालयों

की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनकी प्राथमिकताओं में निवेश आकर्षित करना प्रमुख रहा। उनका मानना था कि प्रदेश के विकास का आधार केवल सरकारी योजनाएं नहीं, बल्कि निजी निवेश, रोजगार और औद्योगिक विस्तार भी होना चाहिए। उन्होंने निवेशकों के बीच मध्यप्रदेश की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनकी कार्यशैली का एक प्रमुख पहलू यह रहा कि वे उद्योग और रोजगार को विकास के प्रमुख साधन के रूप में देखते थे।आज भी प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश की चर्चा के दौरान कमलनाथ के कार्यकाल का उल्लेख किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान

कमलनाथ उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने संसद और केंद्र सरकार में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका निभाई। कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव उन्हें प्राप्त रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रभाव और संपर्क दोनों मजबूत रहे हैं। राज्यसभा जैसे मंच पर उनकी उपस्थिति केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती थी। उनके अनुभव का लाभ प्रदेश के विकास, निवेश और केंद्र-राज्य समन्वय के मुद्दों पर मिल सकता था।

राजनीतिक विरोधियों के बीच भी सम्मान

लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली का सम्मान राजनीतिक विरोधी भी करते हैं। कमलनाथ का नाम ऐसे नेताओं में लिया जाता है। कई अवसरों पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके अनुभव और प्रशासनिक क्षमता का उल्लेख किया है। योजनाओं की निरंतरता विकास की पहचान

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अक्सर सरकारें बदलती हैं, लेकिन जनहित की योजनाएं और विकास की अवधारणाएं आगे बढ़ती रहती हैं। कमलनाथ सरकार के दौरान शुरू की गई कई पहलों और विकास संबंधी विचारों पर बाद की सरकारों ने भी काम जारी रखा। यह किसी भी नेतृत्व की सफलता का संकेत माना जाता है कि उसकी सोच और योजनाएं राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी प्रासंगिक बनी रहे। विकास के क्षेत्र में निरंतरता ही किसी राज्य को आगे बढ़ाती है और इस दृष्टि से कमलनाथ की कई पहलें आज भी चर्चा का विषय हैं।

जनसंपर्क और राजनीतिक अनुभव की बड़ी पूंजी

कमलनाथ की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनका जनसंपर्क और संगठनात्मक अनुभव माना जाता है। दशकों तक सक्रिय राजनीति में रहने के कारण उन्होंने विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के साथ मजबूत संवाद स्थापित किया। उनकी कार्यशैली में व्यावहारिकता और प्रशासनिक समझ दिखाई देती है। यही कारण है कि वे केवल कांग्रेस के नेता नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की राजनीति के एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में देखे जाते हैं।

सवालों के घेरे में भारतीय शिक्षा तंत्र

-प्रमोद कुमार
(वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट)

वर्तमान में पूरे देश में कुछ चर्चा का विषय है तो वह नीट 2026 पेपर-लीक का मामला। वर्तमान केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा जल्दी में पेपर-लीक मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यह दर्शाता है कि सरकार जेन-जी के हमलावर होने से सरकार भयभीत हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एंजेसी (एनटीए) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर-लीक मामला भारत की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बहुत बडा प्रश्नचिन्ह जेन-जी द्वारा लगाये जा रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा नवम्बर 2017 में शिक्षा मंत्रालय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की स्थापना की थी। इसका मुख्य उददेश्य उच्च शिक्षा संसाधनों में प्रवेश एवं फेलोशिप के लिए पारदर्शा और निष्पक्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करनी है। यह एजेंसी शिक्षा मंत्रालय निर्दशानुसार JEE MAIN, NEET UG, UGC-NET AND CUET-UG ,o PG जैसे लगभग 15 प्रवेश प्रमुख परीक्षाएं प्रतिवर्ष आयोजित कराती है। लेकिन आजकल इस एनटीए की विफलताओं पर युवा वर्ग काफी आक्रोशित है। अब तो हमारे युवा सडकों पर उतर गए हैं। 06 जून 2026 को लाखों युवा जन्तर मन्तर पर अपना आक्रोश वर्तमान सरकार तथा एनटीए पर पेपर लीक होने के लिए दिखा रहे हैं। युवाओं ने एनटीए की परिभाषा बड़े तार्किक रुप से बताये हैं। उनका कहना है कि एनटीए का मतलब एन फार नेशनल, टी फार तबाही और ए फार एंजेसी है। जेन-जी का कहना है कि एनटीए हमारे भविष्य के लिए तबाही का रास्ता लेकर आई है। यह एनटीए अपने उददेश्य से पूर्ण रुप से भटक गई है। जिसके परिमाणस्वरुप हम लोगों का आन्दोलन कॉकरोच जनती पार्टी बैनर के नीचे लाखों युवा एकजुट होकर के जन्तर मन्तर पर शिक्षा मंत्रालय की विफलता को जाहिर कर चुके हैं। युवाओं की मांग है वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए एवं इससे सम्बन्धित आधिकारियों के लिए त्वरित कार्रवाई होने चाहिए।

हम कॉकरोचों को उम्मीद थी कि इस विकसित भारत में अरबपति बन जायेंगे। लेकिन भारतीय जनती पार्टी के 12 सालों के शासनकाल में अरबपतियों की संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है और इसकी संख्या मात्र 205 है। जो वर्तमान सरकार के इशारे पर नाचते हैं और 25 करोड़ कॉकरोच अरबपति बनने के लिए कतार में इंतजार कर रहे हैं। भाजपा ने 2014 में एक स्लोगन लेकर आई थी कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन हमारे करोडों युवा वर्तमान में बेरोजगारी के चलते इधर उधर भटक रहे हैं। सरकारी परीक्षा लेने वाली एजेंसी भी भ्रष्ट हो रही है।

उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि ये दुःखद है कि एनटीए ने पहले पेपरलीक से सबक नही सीखा है। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा एजेंसी की जगह एक मजबूत और स्वायत्य निकाय स्थापित करने सम्बधित याचिकाओं पर केन्द्र, एनटीए और सीबीआई से जबाव तलब किया है। शीर्ष अदालत ने ऑल इंडिया मेडिकल एसोशियन द्वारा वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।

जेन-जी की मांग है कि एनटीए में सुधार के लिए गठित राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों पर सरकार गंभीरता से विचार करे। युवाओं की परेशानियों को सरकार गहराई से सुनती ही नही है। हकीकत यह है कि आजादी के बाद भी जितने भी नेता इस शिक्षा पद पर आए, उनकी शिक्षा प्रणाली बनाने और उपयोगी शिक्षा नीति निर्धारण करने में कोई रुचि नही दिखाई है। जिसके परिमाणस्वरुप बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम 1947-1958 तक पढाई-लिखाई के लिए अंग्रेजों की मैकाले पद्धति और प्रारंभिक इस्लामिक शिक्षा को लागू रखने के अलावा कोई उल्लेखनीय कार्य नही किए। पंडित नेहरु के विशेष कृपापात्र होने के चलते उनके नेतृत्व में यूजीसी और वैज्ञानिक शिक्षा की नींव रखी गई लेकिन वे महानुभाव भूल गए कि देश को मजबूत शिक्षा नीति की जरुरत है।

देश ने विश्व स्तरीय उच्च शैक्षणिक संस्थान बनाए लेकिन प्रांरभिक और माध्यमिक शिक्षा को कोई महत्व नही मिला। क्या किसी दल की सरकार ने भी विधार्थियों के भविष्य के लिए कोई गंभीरता से कोई ठोस कदम उठाया है। भारत में पेपर-लीक कानून बने लेकिन अभी तक कोई सकारत्मक कदम नही उठाया है। इस कानून के तहत अपराधियों को 3 से 5 साल और 10 लाख का जुर्माना तथा संगठित लोगों को 5 से 10 साल की सजा तथा 1 करोड का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण यह कानून सरकार के ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। युवाओं में पेपर-लीक होने के कारण मानसिक तनाव होने के कारण युवा अवसाद में चले जाते हैं, यहां तक कि भारत के मासूम और होनहार बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। उदाहरणार्थ अंशिका दिल्ली, आजादपुर, प्रदीप मेघवाल, राजस्थान, शीतल, सिद्धार्थ हेगरे, गोवा और कुछ देश के बच्चे भी इस तरह के कदम में शामिल हैं। इस तरह की धांधली में हमारे देश के कोचिंग संस्थानों का भी काफी हाथ है। ये संस्थाएं पैसे के बल पर अयोग्य छात्रों को योग्य और योग्य छात्रों को अयोग्य कराने के मामले में काफी माहिर हैं। आजकल का शिक्षा व्यापार और पैसे का खेल हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जब तक हमारी शिक्षा पद्धति को शिक्षाविदों तथा विशेषज्ञों के हाथों में ना सौंपा जाए और जबावदेही प्रवेश लेने वाली एजेंसी ईमानदारी से काम न करे तब तक हमारे युवाओं का भविष्य संतोषजनक नही होगा।

मत्स्य पालन से आत्मनिर्भर बन रहे किसान, साय सरकार की पहल ला रही बदलाव

(पेज 1 का शेष)

इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि यदि किसानों को आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण संसाधन और समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। यही सोच आज प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र में दिखाई दे रही है।

जशपुर ने रचा नया इतिहास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर प्रदेश के लिए नई मिसाल प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण पिछले 22 महीनों में जिले ने 22 हजार 805 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल उत्पादन बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हजारों किसानों और मत्स्यपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है तथा मत्स्य आधारित स्वरोजगार को भी नई गति प्राप्त हुई है।

मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम

मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीजों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इसी उद्देश्य से जशपुर जिले में 18.50 करोड़ स्पॉन, 2.55 करोड़ स्टेज फ्राय तथा 2.94 करोड़ मत्स्य बीजों का सफल संचयन किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर मत्स्य बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। किसानों को अब बाहर से बीज मंगाने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जिससे लागत कम हुई है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि दर्ज की गई है।

सात हजार से अधिक हितग्राहियों को मिला सीधा लाभ

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जिले में 77.67 हेक्टेयर तालाब तथा 295.27 हेक्टेयर जलाशयों का पट्टा आवंटित किया गया है। इसके साथ ही नाव, जाल, फिंगरलिंग, मत्स्य बीमा, विपणन सहायता तथा अन्य आवश्यक संसाधनों का लाभ सात हजार से अधिक हितग्राहियों को उपलब्ध कराया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से मत्स्यपालकों को न केवल व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता मिली है, बल्कि अपने कार्य का विस्तार करने और अधिक आय अर्जित करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

आधुनिक तकनीक से बढ़ी उत्पादकता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार मत्स्य पालन को पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण, पौंड लाइनर, बायोफ्लॉक इकाइयों, हैचरी, मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र तथा अन्य आधुनिक संरचनाओं की स्थापना के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इससे आधुनिक तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ा है। बायोफ्लॉक जैसी नवीन प्रणालियों के माध्यम से सीमित क्षेत्र में अधिक उत्पादन संभव हो रहा है। वैज्ञानिक पद्धति अपनाने से उत्पादन लागत में कमी आई है और मत्स्य उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

प्रशिक्षण से बदल रही ग्रामीण तस्वीर

किसानों को केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होता। उन्हें आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के मत्स्यपालकों को देश के विभिन्न राज्यों में एक्सपोजर विजिट पर भेजा जा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को वैज्ञानिक मत्स्य पालन, तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज उत्पादन, संतुलित आहार, जल गुणवत्ता, रोग नियंत्रण, प्रसंस्करण तथा विपणन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिल रही मजबूती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के जिस संकल्प को आगे बढ़ाया गया है, उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ता उत्पादन, स्वरोजगार के नए अवसर, आधुनिक तकनीक का विस्तार और किसानों की आय में वृद्धि इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से ग्रामीण युवाओं का पलायन भी कम हो रहा है। अब गांवों में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है।

समावेशी विकास का प्रभावी मॉडल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विकास मॉडल केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसमें छोटे किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति समुदाय तथा स्वयं सहायता समूहों को भी समान रूप से लाभान्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही कारण है कि मत्स्य पालन का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जिले में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जाए तथा प्रदेश को मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली नई शक्ति

मत्स्य पालन अब केवल सहायक व्यवसाय नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का प्रभावी माध्यम बन चुका है। बढ़ती आय, स्थानीय रोजगार, महिला सहभागिता, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी है। जशपुर की सफलता पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का परिणाम है कि आज हजारों किसान आत्मविश्वास के साथ मत्स्य पालन को अपना रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। आने वाले समय में यदि इसी प्रकार योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रहा तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।

प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र की यह प्रगति केवल उत्पादन बढ़ने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर गांवों, समृद्ध किसानों और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई विकासगाथा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सम्पादकीय

आस्था के केंद्रों की सुरक्षा पर उठते सवाल

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे पवित्र और अत्यधिक सुरक्षा वाले परिसर में चोरी जैसी घटना सामने आना स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र और प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में शामिल अयोध्या राम मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे स्थानों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, आधुनिक निगरानी प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। इसके बावजूद यदि चोरी जैसी घटना होती है, तो यह संकेत है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि केवल सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली, समन्वय और तकनीकी संसाधनों को भी लगातार सुदृढ़ करना होगा।

धार्मिक स्थलों पर होने वाली ऐसी घटनाएं केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहतीं। इनका सबसे बड़ा प्रभाव श्रद्धालुओं के मन में उत्पन्न होने वाली असुरक्षा की भावना पर पड़ता है। लोग यह अपेक्षा करते हैं कि जिन स्थलों पर वे श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, वहां उनकी आस्था के साथ-साथ सुरक्षा की भी पूर्ण गारंटी हो। इसलिए ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष और त्वरित जांच आवश्यक है, ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आज देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक प्रवेश व्यवस्था, डिजिटल मॉनिटरिंग और कमांड सेंटर जैसी व्यवस्थाएं सुरक्षा को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर स्वतंत्र ऑडिट भी होना चाहिए, जिससे संभावित कमजोरियों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर किया जा सके।

सुरक्षा केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर ट्रस्ट, प्रशासन, सुरक्षा बल, स्थानीय कर्मचारी और श्रद्धालु सभी की सतर्कता समान रूप से आवश्यक है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देना, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना और परिसर में अनुशासन बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। इस विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से बचना भी उतना ही आवश्यक है। आस्था से जुड़े विषयों को राजनीतिक विवाद का माध्यम बनाने की बजाय प्राथमिकता इस बात को मिलनी चाहिए कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। संवेदनशील मामलों में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई ही जनता का विश्वास बनाए रख सकती है।

भारत में अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इन सभी स्थलों के लिए एक समान सुरक्षा मानक विकसित किए जाने चाहिए। नियमित सुरक्षा अभ्यास, कर्मचारियों का सत्यापन, आधुनिक तकनीकी उपकरणों का उपयोग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाना समय की मांग है। सुरक्षा व्यवस्था जितनी पारदर्शी और पेशेवर होगी, श्रद्धालुओं का विश्वास भी उतना ही मजबूत होगा। अयोध्या राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। चोरी जैसी घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा विषय हैं। आवश्यक है कि इस घटना से सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाए, तकनीकी और मानवीय दोनों स्तरों पर सुधार किए जाएं तथा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न्यूनतम रह जाए। यही आस्था का सम्मान और सुशासन की वास्तविक कसौटी होगी।

सियासी गहमागहमी

भाजपा की अंदरूनी खींचतान संगठन के लिए चुनौती

मध्यप्रदेश भाजपा लंबे समय से देश के सबसे मजबूत संगठनात्मक ढांचे वाली इकाइयों में गिनी जाती रही है। हालांकि हाल के समय में नेताओं के बीच मतभेद, सार्वजनिक बयानबाजी और संगठनात्मक निर्णयों को लेकर उठ रहे असंतोष ने अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं को हवा दी है। किसी भी बड़े राजनीतिक दल में विचारों का मतभेद स्वाभाविक होता है, लेकिन जब यह सार्वजनिक रूप से सामने आने लगे तो इसका असर संगठन की छवि और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है। भाजपा का सबसे बड़ा आधार उसका अनुशासित संगठन और सामूहिक नेतृत्व की परंपरा रही है। ऐसे में यदि वरिष्ठ नेताओं के बीच असहमति या गुटबाजी की धारणा मजबूत होती है, तो विपक्ष को भी राजनीतिक मुद्दा मिल जाता है। आगामी चुनावों और संगठनात्मक विस्तार को देखते हुए पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती यह होगी कि वह सभी नेताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करे और असंतोष को संवाद के माध्यम से दूर करे। राजनीति में मतभेद से अधिक महत्वपूर्ण उनका समाधान होता है। यदि संगठन समय रहते इन संकेतों को गंभीरता से लेकर सामंजस्य स्थापित करता है, तो यह स्थिति आसानी से संभाली जा सकती है।

कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के भरोसेमंद राजनेता

मध्यप्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का नाम कांग्रेस के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है। लंबे सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ के कारण वे आज भी प्रदेश कांग्रेस के लिए एक भरोसेमंद चेहरा माने जाते हैं। जब भी पार्टी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करती है, कमलनाथ का अनुभव और रणनीतिक सोच चर्चा का विषय बनती है। केंद्र सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहने और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के दौरान उन्होंने प्रशासनिक निर्णयों और विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से अपनी कार्यशैली की छाप छोड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी स्वीकार्यता का एक कारण यह है कि वे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। हालांकि राजनीति में मतभेद और चुनौतियां हर दल का हिस्सा होती हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर कमलनाथ को अभी भी ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है, जो कठिन परिस्थितियों में पार्टी को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उनका अनुभव और राजनीतिक समझ प्रदेश में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

एक और पेपर लीक।
एक और परीक्षा रद्द।
इस बार महाराष्ट्र का TET।
देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
यह सिर्फ पेपर लीक नहीं,
यह युवाओं के भविष्य की चोरी है।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता
@RahulGandhi

मध्य प्रदेश को भाजपा ने भ्रष्टाचार और घोटालों की प्रयोगशाला बना दिया है। ताजा घोटाला गेहूं खरीद में हो गया।
एक तरफ एमपी के किसान स्लॉट बुकिंग को तरसते रहे तो दूसरी तरफ फर्जी किसानों ने प्रदेश के कई जिलों में करोड़ों का गेहूं बेच दिया।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

नई पीढ़ी की राजनीति का उभरता चेहरा है नकुलनाथ

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने पारिवारिक विरासत के साथ-साथ अपनी अलग कार्यशैली और जनसंपर्क के बल पर भी पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ऐसे ही नेताओं में गिने जाते हैं। वे आधुनिक सोच, शांत स्वभाव और विकासोन्मुख राजनीति के समर्थक माने जाते हैं। कम समय में उन्होंने मध्यप्रदेश, विशेषकर छिंदवाड़ा क्षेत्र में अपनी सक्रियता और जनसंपर्क के माध्यम से एक अलग पहचान स्थापित की है। नकुलनाथ का जन्म 21 अप्रैल 1974 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित विद्यालयों में हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और व्यावसायिक क्षेत्र में भी अनुभव अर्जित किया। राजनीति में सक्रिय होने से पहले उन्होंने उद्योग, प्रबंधन और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, जिससे उन्हें प्रशासनिक और आर्थिक विषयों की व्यावहारिक समझ मिली।

राजनीतिक दृष्टि से नकुलनाथ ऐसे परिवार से आते हैं, जिसने कई दशकों तक मध्यप्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पिता कमलनाथ लंबे समय तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। यही कारण है कि बचपन से ही नकुलनाथ का संपर्क सार्वजनिक जीवन और जनसेवा से रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ ने मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और विजयी होकर पहली बार संसद पहुंचे। यह सीट लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है और वहां के मतदाताओं ने उन पर विश्वास व्यक्त किया। सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्रीय विकास, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

नकुलनाथ का राजनीतिक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत शांत और संयमित माना जाता है। वे आक्रामक बयानबाजी की बजाय संवाद और विकास आधारित राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। संसद में भी उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े विषयों के साथ किसानों, युवाओं और उद्योगों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में उनके प्रयासों का केंद्र सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, शिक्षा संस्थानों के विकास तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर रहा है। वे लगातार क्षेत्र के लोगों से संवाद बनाए रखते हैं और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल करते रहे हैं। युवा नेतृत्व के रूप में नकुलनाथ आधुनिक तकनीक और डिजिटल संचार माध्यमों का भी प्रभावी उपयोग करते हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से जुड़े रहते हैं और विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी साझा करते हैं। उनकी कार्यशैली में परंपरागत जनसंपर्क और आधुनिक संचार व्यवस्था का संतुलित समावेश दिखाई देता है। कांग्रेस संगठन में भी उन्हें नई पीढ़ी के प्रमुख नेताओं में देखा जाता है। संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी और युवाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता को पार्टी भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखती है। विशेष रूप से मध्यप्रदेश में कांग्रेस के युवा नेतृत्व को मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नकुलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करना है। लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ती हैं और युवा नेताओं के लिए विकास, पारदर्शिता तथा जनविश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी कसौटी होती है। नकुलनाथ का सार्वजनिक जीवन अभी अपेक्षाकृत प्रारंभिक चरण में है, किंतु उन्होंने अपने शांत व्यक्तित्व, सौम्य व्यवहार और जनसंपर्क के माध्यम से मध्यप्रदेश की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आने वाले वर्षों में उनकी भूमिका कांग्रेस संगठन, मध्यप्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर किस दिशा में विकसित होती है, इस पर राजनीतिक जगत की विशेष नजर रहेगी। नकुलनाथ आज उन युवा नेताओं में शामिल हैं जो अनुभव और नई सोच के समन्वय के साथ राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे जनसरोकारों, विकास और संगठनात्मक मजबूती पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो भविष्य में वे मध्यप्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

परिवार के सपनों का पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्धः विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होने का सपना होता है और राज्य सरकार इस सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केवल गृह निर्माण तक सीमित रहा मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगो का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में आवास बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रा के माध्यम से कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी सहित विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आर्थिक चुनौतियों से उबरते हुए मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडल के अध्यक्ष तथा पूरी टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सभी संकल्पों और वायदों को तेजी से पूरा किया है। सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आज प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद साढ़े दस लाख से अधिक परिवार के आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रतिदिन लगभग 1,600 नए आवास तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से 15 हजार अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए गए हैं तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी विशेष आवास योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'सेवा सेतु' के माध्यम से 450 से अधिक शासकीय सेवाएं अब मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे उपलब्ध हैं। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विभाग में व्यापक प्रशासनिक सुधार लागू किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल को अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में नई पहचान देकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में इसकी भूमिका का विस्तार किया गया है।

नेताओं की बढ़ती संपत्ति पर उठ रहे सवाल, विकास किसका हुआ?

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. नरसिंहपुर। जिले सहित प्रदेश भर में आम लोगों के बीच यह चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है कि राजनीति में आने से पहले कई नेताओं की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन वर्षों बाद उनकी घोषित संपत्तियों में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे में जनता सवाल उठा रही है कि विकास क्षेत्र का हुआ या नेताओं का। ग्रामीणों और नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याएं आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत होती दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि जनता के विकास के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की संपत्तियों की नियमित और पारदर्शी जांच भी होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की संपत्ति में हुई वृद्धि के स्रोत क्या हैं और क्या यह वृद्धि पूरी तरह वैधानिक एवं पारदर्शी है। वहीं राजनीतिक दलों का तर्क है कि संपत्ति में वृद्धि व्यवसाय, कृषि, निवेश और अन्य वैध आय स्रोतों के कारण भी हो सकती है।

शत-प्रतिशत खरीदी जाए मूंग

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। , संवाददाता : भारतीय किसान संघ टिमरनी द्वारा कृषि उपज मंडी परिसर में राधा कृष्ण मंदिर में मासिक बैठक की गई, जिसमें किसानों के हित में विंदुवार विचार विमर्श कर किसानों को आ रही समस्या के निराकरण के लिए 11 सूत्री मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार दिलीप परते को सौंपा। जिसमें भारतीय किसान संघ दीपचंद नवाद ने बताया कि पिछले सीजन गेहूं एवं चने खरीदी में आए संकट को देखते हुए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी शीघ्र प्रारंभ कर, उत्पादित मूंग शतप्रतिशत खरीदा जाना चाहिए, पिछले गेहूं चने के सीजन जैसी सरकार को खरीदी में भूल नहीं करना चाहिए, उस भूल का परिणाम भी सरकार को भोगना पड़ा था। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भुगतान अभी भी शेष है, भुगतान शीघ्र किया जावे। ई-टोकन का समय 3 दिन का किया जावे। सहकारी समिति में सभी प्रकार के खाद उपलब्ध कराए जावे, जिसमें डीएपी खाद प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जावे। सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को 0% ब्याज का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए सहकारी समितियों को पहली प्राथमिकता में खाद उपलब्ध कराया जावे। ज्ञापन देते समय भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष नरेंद्र दोगने, दीपचंद नवाद, रेवाशंकर दोगने, रामकृष्ण राजपूत, राजेश डूडी, कुंवर सिंह राजपूत, जितेंद्र राजपूत, बलवीर राजपूत, मुकेश पटेल, अनिल दोगने, विष्णु मालाकार, राहुल बांके सहित कई किसान मौजूद रहे।

एक चेतावनी है वेनेजुएला का भूकंप

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में एक मिनट के अंतराल पर आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने बड़ी तबाही मचा दी है। 24 जून 2026 को शाम को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों ने पूरे देश की बुनियाद को हिला दिया है। इसे वेनेजुएला का एक सदी में आए सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप का दर्जा दिया गया है। इस शक्तिशाली भूकंप के प्रभाव से राजधानी कराकस और उसके आसपास की सैंकड़ों इमारतें कंक्रीट और स्टील के मलबे में बदल गईं। 188 लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। यूएस भूगर्भीय सर्वेक्षण में कहा गया है कि आशंका है कि 10,000 से भी अधिक लोग इस विनाशलीला में समा गए हो? 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप कैरिबियन तट पर मोरोन के पश्चिम में आया। राजधानी कराकस से करीब 170 किमी की दूरी पर यह स्थल है। भूकंप का केंद्र धरती से 22 किमी नीचे था। ठीक एक मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप आया, यह धरती की 10 किमी गहराई से उभरा था। यह जगह मोरोन से 16 किमी दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। चूंकि यह भूकंप छुट्टी के दिन आया था, इस कारण ज्यादातर लोग बहुमंजिला इमारतों के घरों में थे। इस कारण मौतों का अनुमान 10,000 तक लगाया जा रहा है। इसकी आशंका इसलिए की जा रही है, क्योंकि गुमशुदा लोगों की जानकारी के लिए बनाई गई वेबसाइट पर 66 हजार से भी अधिक लापता लोगों की सूची सामने आ गई। इस भूकंप के झटके जापान और नेपाल में भी दर्ज किए गए हैं।

उथले भूकंप गर्भ से भूमि की सतह पर फूटने के साथ भीषण बर्बादी का कारण बनते हैं। वेनेजुएला का भूकंप 10 और 22 किमी की गहराई से फूटे इसलिए नुकसान ज्यादा होने की आशंका है। भूकंप की चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं लेकिन वह भू-गर्भ में हो रही दानवी हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में लगभग असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं। इसलिए यहां लाख टके का सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना और पाताल की गहराइयों को नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने में क्यों असफल हैं? जबकि वैज्ञानिक इस दिशा में लंबे समय से कार्यरत हैं। अमेरिका एवं भारत समेत अनेक देष मौसम व भू-गर्भीय हलचल की जानकारी देने वाले सैंकड़ों उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। हिंदूकुश क्षेत्र में आया यह भूकंप भारत के लिए भी चेतावनी हैं। लेकिन ये उपग्रह 2025 में आए अफगानिस्तान के भूकंप की तरंगों को नहीं पकड़ पाए थे। दरअसल दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप षामिल है। इसीलिए इस भूकंप को स्थानीय भू-गर्भीय विविधता का कारण माना गया है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविश्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 सालों में एक बार भूकंप आने की आषंका बनी रहती थी, लेकिन अब यह घटकर 04 साल हो गई है। यही नहीं आए भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है, उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा षक्तिषाली हुई है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जो भूकंप आया था, उनसे 20 थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। यहां हुआ प्रत्येक विस्फोट हिरोशिमा-नागाशाकी में गिराए गए परमाणु बमों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। जापान और फिर क्वोटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चला है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रही भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण की अनदेखी प्रकृति को प्रकोप में बदल रही है। इसलिए बाढ़, भू-स्खलन, सूखा, हिमनदों का पिघलना, भूकंप और सुनामी जैसे तूफानों का आना निरंतर बना हुआ है।

भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया इस अभिशाप को झेलने के लिए जब-तब विवश होती रही है। बावजूद हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए जरूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब साढ़े पांच करोड़ साल पहले भारत और आस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक-दूसरे से अलग हो गईं और वे यूरेशिया परत से जा टकराईं। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूद दरारें बनीं। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है, जहां पृथ्वी की दो अलग-अलग परतें परस्पर टकराकर एक-दूसरे के भीतर घुस गई थीं। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसी प्रायद्वीप में ज्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंपों की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किमी भीतर होती है। इससे यह वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाषकारी तरंगें जमीन से कम से कम 30 किमी नीचे से चलती हैं। ये तरंगे जितनी कम गहराई से उठेंगी, उतनी तबाही भी ज्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव भी कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है अब कम गहराई के भूकंपों का दौर चल पड़ा है। मैक्सिको में सितंबर 2017 में आया भूकंप धरती की सतह से महज 40 किमी नीचे से उठा था। इसलिए इसने भयंकर तबाही का तांडव रचा था। तिब्बत में आए भूकंप की गहराई तो मात्र 10 किमी आंकी गई है,अफगानिस्तान का भूकंप मात्र 8 से 10 किमी की गहराई से उठा था, और अब वेनेजुएला में आया भूकंप भी 10 किमी की गहराई से फूटा है।

दरअसल सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने व कम दबाव के कारण कमजोर पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है। कुछ भूकंप धरती की सतह से 100 से 650 किमी के नीचे से भी आते हैं, लेकिन तीव्रता धरती की सतह पर आते-आते कम हो जाती है, इसलिए बड़े रूप में त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। दरअसल इतनी गहराई में धरती इतनी गर्म होती है कि एक तरह से वह द्रव रूप में बदल जाती है। इसलिए इसके झटकों का असर धरती पर कम ही दिखाई देता है। बावजूद इन भूकंपों से ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलती है। धरती की इतनी गहराई से फ्रगट हुआ सबसे बड़ा भूकंप 1994 में बोलिविया में रिकॉर्ड किया गया है। पृथ्वी की सतह से 600 किमी भीतर दर्ज इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। इसीलिए यह मान्यता बनी है कि इतनी गहराई से चले भूकंप धरती पर तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चट्टानें तरल द्रव्य के रूप में बदल जाती हैं। लेकिन कम गहराई से फूटने वाले भूकंप बर्बादी का जलजला धरती पर परोस देते हैं।

आस्था, सुरक्षा और समाज का बदलता विश्वास

-आलोक सक्सेना

हाल के वर्षों में मंदिरों, धार्मिक स्थलों और दान-पात्रों से जुड़ी चोरी अथवा सुरक्षा संबंधी घटनाएँ समय-समय पर चर्चा का विषय बनती रही हैं। ऐसे मामलों को लेकर समाज में चिंता और भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ स्वाभाविक हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल केवल पूजा के केंद्र नहीं बल्कि लोगों की आस्था, विश्वास और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक भी होते हैं। हालाँकि, किसी एक घटना या चित्र के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर चोरी या अव्यवस्था का प्रश्न केवल धर्म से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और सामाजिक जिम्मेदारी का विषय भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सहित सभी धार्मिक संस्थान पारदर्शी व्यवस्था, सुरक्षा उपकरणों और जनभागीदारी को मजबूत करें। दान और चढ़ावा सदैव श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक रहे हैं। यदि कहीं दुरुपयोग या चोरी की घटनाएँ होती हैं, तो उसका समाधान संस्थागत सुधार, जवाबदेही और प्रशासनिक कार्रवाई में तलाशना चाहिए, न कि समाज में भय या विभाजन की भावना को बढ़ाने में। समाज तब मजबूत होता है जब आस्था के साथ विवेक भी जुड़ा हो। धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना केवल प्रबंधन या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का साझा दायित्व है। विश्वास की रक्षा भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, व्यवस्था और सामूहिक जिम्मेदारी से होती है।

कचड़ा प्रकृति की सुंदरता पर काला धब्बा

कचरा केवल सड़क पर पड़ा हुआ गंदा सामान नहीं है, बल्कि यह हमारी लापरवाही का आइना है। यही कचरा हवा को दूषित करता है, पानी को जहरीला बनाता है और मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करता है। जब हम प्लास्टिक, पॉलीथीन और गंदगी को यूँ ही फेंक देते हैं, तब हम केवल अपने आसपास की सफाई नहीं बिगाड़ते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संकट खड़ा कर देते हैं। कचरे का पहाड़ आज अधिकांश जगहों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। देश के शहरों में सलाना 6.2 करोड़ टन से भी ज्यादा कूड़ा निकलता है। कोई शहर या कस्बा इस समस्या से अछूता नहीं है। एक तरफ आज पहाड़ टुट रहे हैं तो दूसरी तरफ कचरे का पहाड़ बन रहे हैं। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या निस्तारण की है। इसकी अनदेखी नही की जा सकती कि हमारे अधिकतर नगर कचरे का सही तरह निस्तारण करने में नाकाम हैं। इस नाकामी से देश की राजधानी दिल्ली अग्रणी है। कचरे का समस्या सिर्फ भारत में ही नही है, दूसरे देशों में भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। दुनिया में जैसे जैसे शहरीकरण की गति तेज होती जा रही है नगरपालिका के स्तर पर बढ़ता कचरा एक कठिन चुनौती पेश कर रहा है। दुनिया शहरों की तरफ अग्रसर हो रही है लेकिन शहरी जीवन शैली के परिणामस्वरूप नगरपालिका के स्तर पर जमा होने वाले ठोस कचरे (एमएसडबल्यू) की तादाद शहरीकरण की दर से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है। विश्व बैंक की रिर्पोट में कहा गया है कि 2.9 अरब लोग दस वर्ष पहले महानगरीय क्षेत्र में रहते थे और प्रति व्यक्ति रोजाना 0.64 किलोग्राम महानगरीय क्षेत्र में रहते थे और प्रति व्यक्ति के हिसाब से रोजाना 1.2 किलोग्राम ठोस कचरा (1.3 अरब टन प्रतिवर्ष) तैयार कर देते हैं। एक रिर्पोट के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में 37.7 करोड़ लोग लोग अनुमानित तौर पर 6.2 करोड़ टन ठोस कचरे का उत्पादन सालाना करते हैं। कचरे की समस्या ने शहरों में भयावह रुप धारण कर लिया है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे की मात्रा कम होता है। मुंबई का सबसे बड़ा कचरे का ढेर 110 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैला देवनार कचरा स्थल है। दिल्ली में गाजीपुर, मुबारक चौक, ओखला में कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं। लेकिन विडंबना यह है कि न तो सरकार और न जनता अपने ही बनाए कचरे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सरकार और जनता दोनों इसके लिए एक दूसरे के सिर थोप देते हैं। कचरे की समस्या का मूल कारण है कि लोग अपने कचरे की जिम्मेदारी नही लेते। लोगों को अपने घर से कचरा निकाल देने भर में रुचि है लेकिन इसके बाद इसका क्या होगा इसकी चिन्ता नही है। जब से देश की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरी हमारी क्रय शक्ति बढ़ती गई। हम पुराने जमाने में चीजों को दोबारा, तिबारा इस्तेमाल करने वाली संस्कृति को भूलते गए। चीजें थोड़ी भी पुरानी होती तुरंत नई चीजें ले लिया जाता है। डिब्बा बंद और प्लास्टिक में पैक चीजों को बेतहाशा खरीदने के चलते हमारा देश कचरे के पहाड़ से दबता चला गया। अब यह कचरा हमें लीलने पर उतारू हो चला है। देश में कचरे का निपटाना, रीसाइक्लिंग आदि की वैसे ही आधी अधूरी व्यवसाएं हैं उपर से हमारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा की कहावत को चरितार्थ कर देता है। अगर हम कचरा ही कम पैदा करें तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। हमें अपनी उपभोक्तावादी संस्कृति को बदलनी होगी। खरीदारी के लिए झोला उठाना होगा। खराब चीजों को फिर से इस्तेमाल की आदत बनानी होंगी। घरेलू कचड़े की मात्रा कम करने के साथ उसके प्रभावी निपटान की विशेषता हासिल करनी होगी। हमे यह नही सोचना चाहिए कि दूर फेंक देने से कचरा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम अगर संकल्प कर लें तो कचरा प्रबंधन को अपने आदत में शामिल कर सकते हैं। 1970 से पहले शहरों और कस्बों से सटे गांवों के किसान किचन से पैदा हुए कचरों को ले जाते थे। और अपने खेतों में कंपोस्ट तैयार करते थे। यह स्वस्थ आदत दो चीजों के चलते खत्म हो गई। एक तो प्लास्टिक युग की शुरूआत से लोगों अपने किचन के कचरे को फेंकना शुरू कर दिया। इससे यह कचरा किसानों के लिए अनुपयोगी हो गया। दूसरी वजह इस परंपरा के खत्म होने की वजह बना सरकार द्वारा उर्वरक पर भारी सब्सिडी देना। हम सभी को इसपर विचार करना चाहिए। सबसे महत्तवपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगें उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। आइए, हम सब यह प्रण लें कि न कचरा फैलाएँगे, न फैलने देंगे। धरती को स्वच्छ रखेंगे, भविष्य को सुरक्षित रखेंगे।

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

'पिता': जीवन का 'पहला योग'

एक तरफ पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है, तो दूसरी तरफ पिता के सम्मान का पर्व 'फादर्स डे'। पहली नजर में ये दोनों विषय अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा गहराई से सोचें तो समझ आता है कि पिता और योग दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पिता हमारे जीवन का पहला जीवंत योग हैं और योग हमारे अस्तित्व का अदृश्य पिता। योग शब्द संस्कृत की 'युज' धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना और जीवन में संतुलन लाना। जरा अपने बचपन की ओर लौटिए। जब हम लड़खड़ाते कदमों से खड़े होना सीख रहे थे, तब जिस मजबूत हाथ ने हमें गिरने और संभलने के बीच संतुलन सिखाया, वही हमारे जीवन का पहला 'आसन' था। पिता जीवन के उस मौन संवाहक की तरह हैं, जो खुद धूप में तपकर हमारे भविष्य को स्थिर आधार देते हैं। जैसे योग का अभ्यास हमें शारीरिक रूप से संतुलित रखता है, वैसे ही पिता की उपस्थिति हमें मानसिक रूप से टूटने नहीं देती।

पिता: जीवन का व्यावहारिक 'प्राणायाम'

योग में प्राणायाम केवल सांसों का अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर की उथल-पुथल को नियंत्रित करने की कला है। ठीक वैसे ही, पिता का अनुशासन, उनके संस्कार और कभी-कभी दिखाई देने वाली उनकी कड़ाई हमारे जीवन का व्यावहारिक प्राणायाम है। जब असफलताओं का तूफान आता है या मन भटकने लगता है, तब पिता की कही एक सहज बात या उनकी गंभीर दृष्टि हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट देती है। योग हमारे अंतःकरण को संतुलित करता है और पिता हमारे चरित्र तथा सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि माताएं अक्सर अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त करती हैं, जबकि पिता का प्रेम अधिकतर मौन और कर्म में दिखाई देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर परिवार की जिम्मेदारी उठाना भी एक साधना है।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

रीढ़ की हड्डी का विज्ञान

चिकित्सा विज्ञान और योग दोनों मानते हैं कि शरीर की मजबूती रीढ़ की हड्डी पर टिकी है। योग उसे लचीला और मजबूत बनाता है। यदि परिवार को एक जीवित इकाई मानें, तो उसकी रीढ़ 'पिता' होते हैं। वे बिना किसी शिकायत के पूरे घर का आर्थिक और भावनात्मक भार उठाते हैं, ताकि बच्चे अपने सपनों को निर्भय होकर जी सकें।

महर्षि पतंजलि के यम और नियम केवल साधकों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य हैं। परिवार की खातिर अपनी इच्छाओं का त्याग करना 'अपरिग्रह' है, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना 'संतोष' है और दिन-रात मेहनत करना 'तप' है। पिता को देखकर जो बच्चा सत्य, अनुशासन और मर्यादा सीखता है, वह अनजाने में ही योग के मार्ग पर चल पड़ता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में 24 घंटों में से केवल 30 से 45 मिनट का नियमित आत्म-निवेश- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव और अनिद्रा जैसी जीवनशैली जनित समस्याओं के विरुद्ध आपके शरीर और मन का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बन सकता है। योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, श्वास, मन और चेतना के बीच संतुलन स्थापित करने की एक समग्र जीवन-पद्धति है। जैसे एक पिता स्वयं धूप में तपकर परिवार की सेहत, सुरक्षा और भविष्य की मजबूत नींव रखता है, वैसे ही अपने शरीर और मन की देखभाल करना भी हमारा पहला कर्तव्य है। याद रखिए, स्वस्थ शरीर और शांत मन ही जीवन के हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी और हर सपने को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने का सबसे मजबूत आधार हैं।

सुंदर, स्वस्थ और सार्थक जीवन का सूत्र

पिता हमें इस संसार में आने का आधार देते हैं और योग हमें इस संसार में संतुलित रहना सिखाता है। जब इन दोनों ऊर्जाओं का मिलन होता है, तो जीवन केवल लंबा नहीं, बल्कि सुंदर, स्वस्थ और सार्थक बन जाता है। पिता का स्नेह और योग का अनुशासन दोनों ही सूक्ष्म हैं। दिखाई कम देते हैं, लेकिन जीवन को भीतर से थामने वाले सबसे मजबूत स्तंभ यही हैं।

पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा: प्रदेश के मुखिया ने थपथपाई जिला नेतृत्व की पीठ

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। जिले में पहली बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वाकांक्षी पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा का सफल उपयोग करते हुए 83 वर्षीय गंभीर मरीज रामसेवक टोकसे को उच्च स्तरीय उपचार के लिए नागपुर स्थित विवेक हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल के पीछे कलेक्टर सोमेश मिश्रा के अथक प्रयास, संवेदनशीलता एवं सतत मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि टोकसे के बीमारी के संबंध में जब मिश्रा को जानकारी हुई तब उन्होंने शासन की इस जीवन रक्षक सुविधा का उपयोग किए जाने हेतु स्वास्थ विभाग की टीम को निरंतर मार्गदर्शित कर मरीज के लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था किए जाने हेतु समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए। उनके निरंतर मार्गदर्शन एवं जिला प्रशासन की त्वरित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मरीज के लिए एयर एंबुलेंस की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मल्टी ऑर्गन फेलियर से पीड़ित मरीज को समय पर उच्च स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध होने से उनके बेहतर उपचार का मार्ग प्रशस्त हुआ। कलेक्टर कलेक्टर के इस सराहनीय प्रयास को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)